चीनी पर पीएम ने बनाया जीओएम

अमर उजाला ब्यूरो

राहत पैकेज पर जल्द फैसला लेगी शरद पवार की अध्यक्षता वाली समिति

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में गन्ना किसानों के गुस्से को देखते हुए केंद्र सरकार इस मामले को जल्द सुलझाने के लिए हरकत में आ गई है। चीनी उद्योग के संकट का हल निकालने का जिम्मा प्रधानमंत्री ने शरद पवार की अध्यक्षता वाली मंत्रियों की एक समिति को सौंप दिया है। राहत पैकेज के मुद्दे पर समिति जल्द अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपेगी। इसमें वित्त और खाद्य मंत्री के अलावा पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली को भी शामिल किया गया है। अभी तक शरद पवार अनौपचारिक तौर पर मंत्रियों के साथ संभावित राहत पैकेज को लेकर बातचीत कर रहे थे। मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के साथ नेशनल फेडरेशन ऑफ को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (एनएफसीएसएफएल) के अध्यक्ष कलप्पा बी अवाडे, महाराष्ट्र राज्य सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष विजय सिंह मोहिते पाटिल व सहकारी चीनी मिलों के प्रतिनिधि भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिले। बैठक में शामिल सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने चीनी मिलों को उबारने के उपाय सुझाने के लिए कृषि मंत्री शरद पवार की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति गठित कर दी है, इसमें वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, खाद्य मंत्री केवी थॉमस के अलावा पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली भी शामिल हैं। सरकार पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम में तेजी लाकर चीनी मिलों को राहत देना चाहती है। यह समिति चीनी उद्योग को उत्पाद शुल्क के आधार पर ब्याज मुक्त कर्ज देने के बारे में विचार करेगी। इसके जरिए चीनी मिलों को कार्यशील पूंजी मिल सकेगी, जबकि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले इस कर्ज पर ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। इसके पहले सरकार इसी तर्ज पर मिलों को 3,800 करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया करा चुकी है।

रॉ शुगर के आयात शुल्क में बढ़ोतरी, पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम में तेजी लाने और चीनी के अधिक स्टॉक के मद्देनजर 6 महीने का बफर स्टॉक बनाने जैसे उपायों पर अपनी रिपोर्ट देगी। शरद पवार हाल ही में इस मुद्दे पर वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और खाद्य व वाणिज्य सचिवों के साथ बैठक कर चुके हैं। यूपी की तरह महाराष्ट्र में भी कई चीनी मिलों ने पेराई शुरू नहीं की है और गन्ना किसान दाम बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहां भी चीनी मिलें दाम बढ़ाने और सरकारी रियायतों के बिना पेराई शुरू करने को राजी नहीं हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात में सहकारी चीनी मिलों ने ब्याज मुक्त कर्ज के अलावा चीनी निर्यात पर 500 रुपये प्रति क्विंटल सब्सिडी देने, रॉ शुगर का आयात पूरी तरह बंद करने और 6 महीने का बफर स्टॉक बनाने की मांग रखी है।

अमर उजाला

27/11/13